THE MINISTER OF STEEL **AND** MINES (SHRI K.C. PANT): fa) yes, Sir.

(b) The losses suffered by HSCL during the last three years are as ander:

Year	Rs. in crores
1983-84	16·1
1984-85	2.9
1985-86 (Estimated).	12·7

The surplus manpower has been the major factor for losses in HSCL. In addition, the HSCL also incurred losses in the foreign works in Libya.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि विकास

1644. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्वी क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी धनराशि के व्यय होने की संभावना है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार योजना को कब तक मंजूरी दे देगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) राज्य की समग्र सातवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में कृषि के विकास की ओर विशेष ध्यान देने के लिए एक उपयोजना तैयार की है। प्रस्ताव है कि आदानों के उपयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी संबंधी आधार को सुदृढ़ करने के अलावा, छोटे और सीमान्त किसानों की उत्पादन क्षमता में सुधार करने, ऊसर भूमि का सुधार करने, बारानी खेती की प्रौद्योगिकी को अपनाने, फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्र को आवृत्त करने आदि के उद्देश्यों वाले विशेष कार्यक्रमों की सहायता से पूर्वी क्षेत्र में फसलों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जाए।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1985-86 से 102 चुनिन्दा ब्लाकों में चलाये जा रहे विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

क्षेत्रीय विकास के लिए योजना आयोग द्वारा कोई विशेष आबंटन नहीं किया जाता। योजना आयोग द्वारा समूचे राज्य के लिए सातवीं योजना के प्रस्ताव पर, उपाध्यक्ष, योजना आयोग और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच 14 मई, 1985 को हुई बैठक में विचार किया गया था। योजना आयोग द्वारा जारी किये गए सातवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार सहकारिता सहित कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए कुल 786.96 करोड़ रुपये के परिव्यय का आबंटन किया गया है।

Planning of Irrigation Schemes

1645. SHRI D.B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news report that appeared in the Indian Express of 9th July, 1986 according to which the Prime Minister has strongly criticised the planning of the irrigation schemes in the country; and

(b) if so, what further step-Government propose to take to comp lete the pending major and me